

#06 विदेशी निवेश में कटौतियां

संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दिए जाने के कारण भारत में विदेशियों का नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है। यह क़ानून भारत के संवेदनशील क्षेत्रों में FDI पर रोक लगाकर सिर्फ़ सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति देता है। कृपया ध्यान दें कि यह क़ानून सभी क्षेत्रों में FDI पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता, बल्कि सिर्फ़ संवेदनशील क्षेत्रों में FDI पर निर्वन्धन लगाता है। इस क़ानून को संसद से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके गेज़ेट में छ़ापा जा सकता है। इस क़ानून का पूरा ड्राफ़्ट इस लिंक पर देखें – [Tinyurl.com/ReduceFDI](https://tinyurl.com/ReduceFDI)



प्रस्तावित विदेशी निवेश में कटौतियां क़ानून के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

कोई भी कंपनी अपने आप को वोइक यानी सम्पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कम्पनी (Woic = Wholly Owned by Indian citizens Company) के रूप में पंजीकृत करवा सकती है। वोइक कम्पनी से आशय ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके 100% अंश (Share) भारतीय नागरिकों या भारतीय सरकार या किसी अन्य वोइक कंपनी के पास हों, और अमुक कम्पनी के कोई भी शेयर विदेशियों के पास न हों। निचे दिए गए क्षेत्रों में सिर्फ़ वोइक कम्पनियां ही कारोबार करेगी।

1. सिर्फ़ वोइक कम्पनियां ही संचार एवं मीडिया के क्षेत्र में काम कर सकेगी। संचार एवं मीडिया में सभी पाठ्य, दृश्य, श्रव्य माध्यम जैसे अख़बार, मैगज़ीन, चैनल्स, फ़िल्में, इंटरनेट सेवाएं, सोशल मीडिया एवं टेलिकॉम आदि शामिल हैं।
2. गैर वोइक कम्पनी को भारत में बैंक एवं बीमा कम्पनी खोलने या ऐसी कोई भी वित्तीय कम्पनी खोलने की अनुमति नहीं होगी जो जमाएं (Deposits) स्वीकार करती है। राष्ट्रियकृत बैंक (Nationalised Bank) सिर्फ़ वोइक कम्पनी को ही कर्ज दे सकेंगे।
3. सिर्फ़ वोइक कम्पनियां ही रेलवे, सेटलाइट एवं रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करेगी। रक्षा उत्पादन में हथियार निर्माण एवं सैन्य उपकरण शामिल हैं।
4. सिर्फ़ वोइक कम्पनी को ही खनन (Minerals) एवं ऊर्जा (Power) के क्षेत्र में काम करने की अनुमति होगी।
5. सिर्फ़ वोइक कम्पनियां ही शैक्षिक निकाय, शिक्षा बोर्ड, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोल सकेगी।
6. गैर वोइक कम्पनी भारत में कोई भी भूमि एवं निर्माण नहीं खरीद सकेगी, और न ही इन्हें 25 साल से अधिक अवधि के लिए किराये पर ले सकेगी।
7. मॉरीशस संधि, फिजी संधि, सिंगापुर संधि एवं इस प्रकार की सभी संधियां जो विदेशी पूँजी पर कम दर से आयकर, या कम दर से पूंजीगत लाभ कर लगाती हैं, अब से निरस्त की जाती हैं।

[टिप्पणी : यदि इस खंड की कोई धारा विश्व व्यापार संगठन (WTO) के किसी समझौते का उल्लंघन करती है तो WTO भारत को समझौते से बाहर कर सकता है, या प्रधानमंत्री भारत को WTO समझौते से अलग करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकते हैं।]